



## अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन वधियक, 2023

### प्रलिम्स के लिये:

अपतटीय खनन क्षेत्र, [MMDR \[खान और खनजि \(विकास और वनियमन\)\] अधनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र](#)

### मेन्स के लिये:

अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन वधियक, 2023

## चर्चा में क्यों?

राज्यसभा ने हाल ही में अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) संशोधन वधियक, 2023 पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत के अपतटीय खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना है।

- यह संशोधन मौजूदा अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) अधनियम, 2002 को संशोधित करने का प्रयास करता है, ताकि अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकार आवंटित करने की वधि के रूप में नीलामी को सक्षम किया जा सके।

## संशोधन वधियक की मुख्य विशेषताएँ:

- नीलामी व्यवस्था का परिचय:**
  - दो प्रकार के परिचालन अधिकार, उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस, विशेष रूप से नज्दी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से दिये जाएंगे।
  - केंद्र सरकार द्वारा आरक्षणित खनजि क्षेत्रों में सार्वजनिक उपकरणों को संचालित करने के अधिकार दिये जाएंगे। सार्वजनिक उपकरणों को मूलतः परमाणु खनजि के परिचालन अधिकार भी प्रदान किये जाएंगे।
    - परमाणु खनजि में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, दुर्लभ धातुएँ जैसे खनजि शामिल हैं। नओबियम, टैंटलम, लथियम, बेरलियम, टाइटेनियम, ज़रिक्ोनियम और [दुर्लभ मृदा तत्व \(REE\)](#) के साथ-साथ समुद्र तट के रेत खनजि।
- उत्पादन पट्टे (Production Lease) की नरिधारति अवधि:**
  - उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है।
  - उत्पादन पट्टे की अवधि [खान और खनजि \(विकास और वनियमन\) अधनियम, 1957 \(MMDR अधनियम\)](#) के तहत 50 वर्ष नरिधारति की गई है।
- क्षेत्र अधगिरहण सीमा:**
  - संपूर्ण अपतटीय क्षेत्र जसि एक संस्था (One Entity) अधगिरहीत कर सकती है, को पृथक रखा गया है।
  - एक या अधिक परिचालन अधिकारों के तहत कसि भी खनजि या संबंधित खनजि के नरिधारति समूह के लिये अधिकतम अधगिरहण क्षेत्र 45 मिनट अक्षांश और 45 मिनट देशांतर तक सीमित है।
- गैर-व्यपगत अपतटीय क्षेत्र खनजि टरस्ट:**
  - अन्वेषण, आपदा राहत, अनुसंधान और प्रभावित पक्षों हेतु लाभ सुनिश्चित करने के लिये एक गैर-व्यपगत अपतटीय क्षेत्र खनजि टरस्ट की स्थापना की जाएगी।
  - टरस्ट को खनजि उत्पादन पर अतरिकित लेवी द्वारा वतितपोषित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा नरिधारति दर के साथ रॉयल्टी के एक-तहिाई से अधिक नहीं होगी।
- व्यवसाय में आसानी तथा समय-सीमा:**
  - कम्पोजिट लाइसेंस या उत्पादन पट्टे के आसान हस्तांतरण के प्रावधान।
  - उत्पादन की समय पर शुरुआत सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन पट्टे के नषिपादन के बाद उत्पादन शुरु करने के साथ प्रेषण के लिये समय-सीमा।
- राजस्व:**
  - अपतटीय क्षेत्रों में खनजि उत्पादन से रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम तथा अन्य राजस्व भारत सरकार को प्राप्त होंगे।

## ऐसे संशोधन वधियक की आवश्यकता क्यों?

- अपतटीय क्षेत्रों में गतविधिका अभाव:
  - अपतटीय क्षेत्र खनजि (विकास और वनियमन) अधनियम, 2002 के अधनियमन के बावजूद अपतटीय क्षेत्रों में कोई खनन गतविधि नहीं हुई है।
  - यह भारत के लिये उपलब्ध विशाल समुद्री संसाधनों के प्रतारुचि अथवा इसके प्रभावी उपयोग की कमी को दर्शाता है।
  - संशोधन वधियक अंतरनहिति मुद्दों को संबोधति करने के साथ इन अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण तथा खनन को प्रोत्साहति करने का प्रयास करता है।
- वविक एवं पारदर्शति का अभाव:
  - वर्तमान अधनियम स्ववविक की समस्या से ग्रस्त है, साथ ही अपतटीय क्षेत्रों में खनन के परचालन अधिकारों के आवंटन में पारदर्शति का अभाव है।
  - संशोधन वधियक का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्रों के लिये MMDR अधनियम में सफल संशोधनों से प्रेरति होकर परचालन अधिकार आवंटति करने हेतु एक पारदर्शी नीलामी तंत्र शुरु करना है।
- समुद्री संसाधनों का दोहन:
  - भारत एक अद्वितीय समुद्री स्थति रखता है। इसमें 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है जो पुनरप्राप्त करने योग्य संसाधनों से समृद्ध है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) का अनुमान है कि विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में चूना मट्टि, नरिमाण हेतु रेत, भारी खनजि, फॉस्फोराइट एवं पॉलीमेटेलिक फेरोमैगनीज़ नोड्यूल और क्रस्ट के महत्त्वपूर्ण भंडार हैं।
  - हालाँकि इन संसाधनों की क्षमता काफी हद तक अपर्युक्त है। संशोधन वधियक सार्वजनिक एवं नजि दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देकर भारत की उच्च विकास अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिये इन समुद्री संसाधनों की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहता है।

## नषिकर्ष:

- इस वधियक का उद्देश्य परचालन अधिकारों के आवंटन करने की वधिके रूप में नीलामी को सक्षम कसारदर्शति को बढ़ावा देना, नजि क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षति करना तथा आर्थिक विकास महत्त्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिये भारत के समुद्री संसाधनों को अनुकूलति करना है।
- यह सुधार सतत और सुरक्षति खनन प्रथाओं को सुनश्चिति करते हुए अपने विशाल समुद्री संसाधनों का दोहन करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

## स्रोत: पी.आई.बी.